राजस्थान को 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए आमजन दें सुझाव:गहलोत

6 सितम्बर से शुरू होगी मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना

लोकजीवन न्यूज नेटवर्क, जयपुर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की अनूठी जनकल्याणकारी योजनाओं की आज हर तरफ चर्चा हो रही है। राईट टू हेल्थ, ओपीएस, न्यूनतम आय गारन्टी कानून जैसे निर्णयों से राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, विद्युत, चिकित्सा, सड़क सहित हर क्षेत्र में राजस्थान ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2030 तक राजस्थान को सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिशन 2030 के विजन पर काम कर रही है। इसमें राज्य के 1 करोड़ लोगों से उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। प्राप्त सुझावों का विजन डॉक्यूमेन्ट बनाकर इसे जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री गंगापुर सिटी में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक-2023 के जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के अवलोकन के दौरान वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने गंगापुर सिटी के जिला बनने पर बधाई देते हुए कहा कि अब क्षेत्र के लोगों को अपने कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहां जिला कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय खुलने से आमजन के कार्य सुगमता से होंगे तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 6 सितम्बर को भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारम्भ किया जाएगा, जिसके तहत प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का प्रति पशु 40-40 हजार रूपए का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गौवंश के संरक्षण के लिए कई

उल्लेखनीय कार्य किए हैं। गौशालाओं एवं नंदीशालाओं को वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग 3 हजार करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया है। लम्पी रोग से मृत गायों पर पशुपालकों को प्रति गाय 40 हजार रूपए का मुआवजा दिया गया। साथ ही, दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध पर प्रति लीटर 5 रूपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिए सरकार ने उठाए पर्याप्त कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि कोयले की कमी तथा अगस्त माह में बारिश कम होने से बिजली की मांग बढ़ने के कारण बिजली की अल्पकालीन समस्या उत्पन्न हुई है, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठा लिए हैं तथा जल्द ही पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी।

सभी क्षेत्रों में हुआ उल्लेखनीय विकास-

गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पिछले साढ़े चार सालों में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें 130 गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं। 500 बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन पर कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनाई जा रही हैं। गहलोत ने कहा कि जिस प्रकार पूर्ववर्ती केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार के अधिकार दिए गए, उसी तर्ज पर राज्य में आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाकर दिया गया है। केंद्र सरकार को भी कानून बनाकर समाज के गरीब, वृद्धजन तथा वंचित तबके को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। न्यूनतम पेंशन बड़ाकर 1000 रुपए की गई है। साथ ही, इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इस दौरान गहलोत ने बालघाट उपतहसील को तहसील बनाने की घोषणा की। जिलास्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के तहत रस्साकशी तथा कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल का शुभारंभ कर अवलोकन किया एवं खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री सलाहकार एवं विधायक रामकेश मीणा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गंगापुर सिटी को जिला बनाने की मांग 74 वर्ष पुरानी थी। मुख्यमंत्री ने यह मांग पूरी कर जन भावना का सम्मान किया है। इससे पूर्व गहलोत ने गांधी दर्शन गैलरी का अवलोकन किया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आमजन ने हेलीपेड से सभास्थल तक पुष्प वर्षा कर गंगापुर सिटी को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्य म में प्रभारी मंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल जाटव, विधायक पीआर मीना, इंदिरा मीना, लाखन सिंह मीना सहित जनप्रतिनिधि, उच्चाधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे केन्द्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। केंद्र सरकार को शीघ्र ही ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए।

केन्द्र भी 500 रूपए में उपलब्ध करवाएं गैस सिलेण्डर -

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों सहित लगभग 76 लाख परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाकर महंगाई से राहत दे रही है। केन्द्र सरकार को भी उज्ज्वला योजना से तहत परिवारों को 500 रूपए में गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से प्रदेशवासियों को कमर तोड़ महंगाई से राहत दी गई। इन कैम्पों में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया गया तथा 7 करोड़ 82 लाख से अधिक गारन्टी कार्ड वितरित किए गए।

जीवन में व्यक्तिगत वित्त का प्रबंध जरूरी - प्रो. सक्सैना

भीलवाड़ा। प्रबंध अध्ययन संकाय, संगम विश्वविद्यालय में विशेषयज्ञ वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वित्त प्रबंधन व्यवसाय प्रबंधन का महत्व पूर्ण हिसा है। प्रो विभोर पालीवाल ने स्वागत भाषण में बताया कि विद्यार्थियों के सर्वांगिन विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की शुरुआत की गई। सत्र के मुख्य वक्ता वनस्थली विधापीठ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अधिष्ठाता डॉ. हर्ष पुरोहित ने वित्त के ऊपर अपना सत्र प्रस्तुत किया। प्रोफेसर पुरोहित ने लोक वित्त एवं निजी वित्त के ऊपर अपना व्याखान प्रस्तुत करते हुए बताया की जीवन में व्यक्तित्व वित्त का प्रशासन आवश्यक है। सेशन के अंत में डॉ. मुकेश शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया तथा बताया कि मैनेजमेंट स्टडीज में इस सत्र से एनआईएसएम सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए गए हैं। सत्र का समन्वय डॉ. ज्योति दशोरा तथा डॉ. रेखा स्वर्णकार ने किया।इस अवसर पर विभाग से सभी संकाय उपस्थिति थे।

बारिश की कमी से फसलों को पहुंचा नुकसान, मुआवजे की मांग

बनेड़ा। उपखंड क्षेत्र के बालेसरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में बारिश की कमी के चलते खराब हो चुकी फसलों की गिरदावरी करवा कर के प्रभावित किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर ग्राम सेवा सहकारी समिति क्षेत्र के किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम सेवा सहकारी समिति बालेसरिया अध्यक्ष भंवर सिंह राणावत के नेतृत्व में एसडीएम नेहा छीपा को सौंपे अपने ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र में करीब डेढ़ माह से बारिश के नहीं होने से किसानों द्वारा खेतों में बोई गई मक्का, उड़द, मूंग, तिल्ली, ग्वार, ज्वार, कपास तथा मूंगफली की फसल पानी की कमी के चलते सुख कर नष्ट हो गई है। साथ ही बारिश की कमी के चलते जलाशयों में भी पानी की कमी के चलते पशुओं के लिए चारे पानी का भी संकट गहराने लगा है। ग्राम पंचायत बालेसरिया एवं राजस्व ग्राम दाता निलावरी, पायरा,दूदला, तथा हाथीपुरा गांवों में फसलें खराब हो चुकी है। अतः शीघ्र खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवा के प्रभावित किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जीएसएस उपाध्यक्ष भंवरलाल गुर्जर, जमना लाल गुर्जर, सत्यनारायण गुर्जर, रामेश्वर बलाई, निर्मल कुम्हार, सत्यनारायण सिंह, नरेश गुर्जर, भगवान गाडरी, परशराम गुर्जर, शिवराज गुर्जर, सांवरा तेली, रतन गुर्जर, दीपक शर्मा, रामजु पिनारा, शंकर गुर्जर मदन तेली सहित अन्य जने उपस्थित थे।

रंजन पोलिस्टर्स लिमिटेड

कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर (सीआईएन): L24302RJ1990PLC005560

पंजीकृत कार्यालय: 11-12TH, की. मी. स्टोन, चित्तौड़गढ़ रोड, गुवारड़ी, भीलवाड़ा -311001(राजस्थान), इंडिया, वेबसाइट:-www.ranjanpolysters.com

फ़ोन: 01482-297133, ई-मेल: ranjanpoly@gmail.com

33वीं वार्षिक साधारण सभा रिमोट ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 33वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, 30 सितंबर, 2023को दोपहर 04:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 11-12TH, की. मी. स्टोन, चित्तौड़गढ़ रोड, गुवारड़ी, भीलवाड़ा -311001(राजस्थान) में आयोजित होना निश्चित की गयी है । कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 एवं सेबी द्वारा जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 जिसकी अनुपालना में 33वीं वार्षिक साधारण का एजीएम नोटिस एवं ई-वोटिंग से सम्बंधित विस्तृत निर्देश व जानकारी के साथ ही वितीय वर्ष 2022-2023 हेतु वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कंपनी/आरटीऐ/डेपोजिटरी के पास पंजीकृत है, ई-मेल द्वारा भेजी गयी है । वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम का नोटिस ई-मेल 5 सितंबर, 2023 तक प्रेषित कर चुके है। एजीएम की सार्वजनिक सूचना एवं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 कंपनी की वेबसाइट www.ranjanpolysters.com और एम स इ आई लिमिटेड की वेबसाइट www.msei.in पर उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएँ) नियमावली, 2015 की नियमावली 44 के अनुपालन में, सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के मंच के द्वारा कंपनी की 33वीं वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित सभी व्यापारिक लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान की गयी है । सदस्य, आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य जगह (रिमोट ई-वोटिंग) से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली का उपयोग करके वोट दे सकते है ।रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी तथा शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 सायः 5.00 बजे समाप्त होगी। । इस समय और दिनांक के अलावा कोई ई-वोटिंग स्वीकार नही की जाएगी। जिन व्यक्तियों का नाम अंतिम तारीख 23 सितंबर, 2023 को सदस्यो अथवा लाभकारी मालिको के रजिस्टर में है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ वोटिंग सुविधा को अधिकृत कर सकते है । सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट दिया है वे भी सभा में सम्मिलित हो सकते है लेकिन वापस सभा में वोट देने का अधिकार नही है ।सूचना के प्रेषण के बाद वे व्यक्ति जिनके पास कंपनी के शेयर एवं सदस्य है उन्हें रिमोट ई-वोटिंग के लिए यूजर आई. डी. तथा पासवर्ड कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बीटल फाइनेंसियल और कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 'बीटल हाउस' तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, बी एच - लोकल शॉपिंग काम्प्लेक्स, दादा हरसुखदास मंदिर के समीप, न्यू दिल्ली - 110062 द्वारा प्राप्त होंगे । यूजर आई.डी.और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है । वार्षिक साधारण सभा में मतपत्र द्वारा मतदान उन सदस्यो को उपलब्ध है जो इस सभा में सम्मिलित है तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नही दिया है । ई- वोटिंग के परिणाम कंपनी के वार्षिक साधारण सभा में अथवा बाद में घोषित किया जायेगा । सदस्यो की सूचना के लिए संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट को सूचित किया जायेगा । ई-वोटिंग से सम्बंधित कोई प्रश्न अथवा मामलों को www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग के 'पूछे जाने वाले प्रश्न' (FAQ) तथा ई-वोटिंग मार्गदर्शक अथवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख कर भेज सकते है । हेल्पडेस्क के टोल फ्री नंबर 1800 -200 -5533 द्वारा भी संपर्क किया जा सकता है ।कृपया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा मतदान की सुविधा से जुडी किसी भी शिकायत के मामले में सीडीएसएल, ए-विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मील कंपाउंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर पारेल (ईस्ट), मुम्बई-400013, ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com , हेल्प डेस्क नंबर 022-23058542/43 पर संपर्क करे। आगे की सूचना एतदद्वारा दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्कताएँ) नियमावली, 2015 की नियमावली 42 के अनुसार कंपनी के सदस्यो के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स सोमवार 25, सितंबर, 2023से शनिवार 30, सितंबर 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। ।

बोर्ड की आज्ञानुसार

रंजन पोलिस्टर्स लिमिटेड के द्वारा

Sd/-

(महेश कुमार भीमसरिया)

प्रबंध संचालक

DIN-00131930

दिनांक: 5 सितंबर, 2023

स्थान: भीलवाड़ा